

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 142/2017 राजस्व अपील

1. कजोड पुत्र मूल्या जाति कोली निवासी कोरडा खुर्द तहसील सिकराय जिला दौसा
अपीलान्त

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार, उप तहसील बहरावण्डा तहसील सिकराय
जिला दौसा

रेसपोडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय उप तहसीलदार उपतहसील बहरावण्डा निर्णय दिनांक 12.09.2017
प्रकरण उनवानी सरकार बनाम कजोड प्रकरण संख्या 232/2017

उपस्थिति : श्री निर्मल कुमार शर्मा अधिवक्ता अपीलान्त उप0।

: श्री चन्द्रशेखर टापरिया, राजकीय अधिवक्ता उप0।

:- निर्णय :-

दिनांक: 28.02.2018

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्त के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि अपीलान्त अतिक्रमी द्वारा ग्राम कोरडा खुर्द तहसील सिकराय में स्थित चारागाह भूमि खसरा नंबर 279 रकबा 0.16 है0 पर कमरा, बाडा का निर्माण एवं गेहूं की काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है तथा अतिक्रमी का भूमि पर कब्जा पश्चातवर्ती है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त अतिक्रमी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्त अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 12.09.2017 को बेदखल कर 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से भी दण्डित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 12.09.2017 से व्यथित होकर अपीलान्त द्वारा यह अपील पेश की गई है।



अति० जिला कलक्टर
दौसा



प्रकरण संख्या : 142/2017 राजस्व अपील

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोंडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्त ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि विरुद्ध एवं प्रक्रिया नियमों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई जांच किये बिना अपीलान्त को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये व बिना पटवारी हल्का से जिरह का अवसर दिये बिना व बिना कोई अन्य कोई स्वतंत्र साक्ष्य लिए पटवारी हल्का की रिपोर्ट को सही मानकर निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात (शपथ पत्र कब्जा काशत नही होने का) अवलोकन नहीं करते हुए निर्णय पारित किया है। निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। अपीलान्त के पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने से संबंधित कोई दस्तावेजात पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। अपीलान्त का किसी चरागाह भूमि पर अतिक्रमण नहीं है। इस बाबत शपथ पत्र भी प्रस्तुत कर दिया जावेगा। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर प्रश्नगत निर्णय खारिज फरमाया जावे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्त अतिक्रमी द्वारा ग्राम कोरडा खुर्द तहसील सिकराय में स्थित राजकीय चारागाह भूमि खसरा नंबर 279 रकबा 0.16 है0 पर कमरा, बाडा का निर्माण एवं गोहू की काशत कर अतिक्रमण करने पर अपीलान्त अतिक्रमी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्त अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 12.09.2017 को बेदखल कर 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 30 दिन का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिक्रमी है।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

अति० जिला कलक्टर
लौसा




प्रकरण संख्या : 142 / 2017 राजस्व अपील


अपीलान्ट के विरुद्ध भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया की अपीलान्ट द्वारा राजकीय चारागाह भूमि पर से अतिक्रमण हटा लिया गया है तथा भविष्य में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया जावेगा। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट इस शर्त पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम कोरडा खुर्द तहसील सिकराय में स्थित राजकीय चारागाह भूमि खसरा नंबर 279 रकबा 0.16 है0 पर से अतिक्रमण हटा लिया जाने एवं भविष्य में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने बाबत शपथ पत्र उप तहसीलदार बहरावण्डा के समक्ष प्रस्तुत करने एवं उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा अतिक्रमण हटा लिया जाना सत्यापित किया जाने पर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.09.2017 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर प्रविष्ट लेख भण्डार हो।




(राजवीर सिंह चौधरी)
अति० जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 28.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(राजवीर सिंह चौधरी)
अति० जिला कलेक्टर, दौसा

